SHRI JIBON ROY: The revival of NTC mills. ...*(Interruptions)*... A new agreement was signed. But no step has been taken by the Government of India on the question of revival. There is an objection only to the method of selling the land. Why don't the Government lease out the land?

If they lease out the land, they will get much more funds out of it. It is within the powers of the Central Government. I would like to know what steps the Central Government is taking to convince the Government of Maharashtra about the matter. If there is any problem in Maharashtra, why have steps not been taken in the case of other States? Let steps be taken in other places. In the meantime, you can think about Maharashtra.

SHRI R.L. JALAPPA: I had gone to hon. Chief Minister twice. I had a full discussion with him along with his other Ministers, Chief Secretary and others. I explained to them all the pros and cons of this project. *(Interruptions)*... Let me reply. *(Interruptions)*... Let me reply. *(Interruptions)*... If they don't want any reply, all right. *(Interruptions)*... I can't help that. *(Interruptions)*...

SHRI AJIT P.K. JOGI: We are talking of the NTC. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one minute. I will call you.

SHRI R.L. JALAPPA: The hon. Member has raised a question. If there is any problem in Maharashtra, why don't we try to do it in other States? Yes, Sir, I have tried it. I don't know whether he has seen it. We have invited tenders for two subsidiaries, Tamil Nadu and APPKM. What has happened is this. In the case of Tamil Nadu the rates were very less. They rejected the tender. In the case of APPKM in Andhra Pradesh they have gone to court. In Kerala the Chief Minister has made a statement that he is not going to allow the land to be sold. Some of the people have gone to the High Court and got a stay order. All these problems are there. I am not sleeping. *(Interruptions)*... But the problem is serious. *(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Minister, nobody said that you were sleeping. *(Interruptions)*...

SHRI R.L. JALAPPA: Sir, getting a plan drafted is very easy. But to get it executed is really a problem. *(Interruptions)*... To ride a horse we require four horseshoes. With only one horseshoe, we cannot ride a horse. *(Interruptions)*...

SHRI JIBON ROY: Why is the Government not taking the route of lease? They should lease out the land. *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Question No. 165.

Inclusion of Telecommunication in Definition of Infrastructure

*165. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS be please to state:

(a) whether it is a fact that Government have included tele-communications in the definition of infrastructure for getting the establishment benefits; and

(b) if so, whether manufacture of cables, tele-communications equipments, paging services, mobile trunk services and the allied activities will also be covered under the umbrella of tele-communications so as to make available the various benefits of the infrastructure sector?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) दूरसंचार को प्राथमिकता का क्षेत्र मानने की सरकार की समग्र नीति के अनुरूप तथा अत्यधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सैल्यूलर तथा बुनियादी दूरसंचार सेवा उद्योग को आधारभूत अवसंरचना मानने का निर्णय लिया गया है। जिससे उन्हें कतिपय वित्तीय लाभ मिल सकेंगे।

(ख) जी नहीं। केवल सैल्यूलर तथा बुनियादी सेवा उद्योगों को ही शामिल किया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल: माननीय सभापति महोदय, 13 मई, 1994 को सैंट्रल टेलिकॉम [illegible] इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत की गई थी। उस समय 8वीं पंचवर्षीय

योजना के जो संशोधित लक्ष्य थे, उसमें यह लिखा था:—

> "Telephones should be available on demand by 1997. All villages should be covered by 1997. In urban areas, a PCO should be provided for every 500 persons by 1997. All value added services available internationally should be introduced in India to raise the telephone services in India to international standards well within the Eighth Plan period preferrably by 1996."

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस संबंध में गतवर्ष भी इस सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी और आपने उस समय भी यह आश्वासन दिया था और हम आपके आश्वासन के भरोसे हैं कि जो कुछ गत दो-तीन वर्षों में गड़बड़ियां हुई इस विभाग में, जो फॉल्टी, टार्डी और शेडी इम्प्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का हुआ, उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मेरे पास कोई कारण नहीं है इस बात की शंका करने का कि आप ईमानदारी से चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंततोगत्वा इस बात में सफल हो गए कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के पैरा नम्बर 103 में इस टेलीकम्युनिकेशन को इन्फ्रास्ट्रक्चर में शामिल कर लिया है और टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन साथ ही वित्त मंत्री महोदय ने अपने पैराग्राफ 122 में कहा है:—

> "Reduction of duty on telecom equipments from 40 per cent to 30 per cent and on their parts from 30 per cent to 20 per cent.

अपनी जो नेशनलन टेलिकॉम पॉलिसी थी, सभापति महोदय, उस टेलिकॉम पॉलिसी में ही यह लिखा हुआ है:—

> "Taking into account India's size and development, it is necessary to ensure that India emerges as a major manufacturing base and a major exporter of telecom equipments."

अब आप के आज के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यह जो टेलिकॉम पॉलिसी का पोरशन है, टेलिकॉम इक्विपमेंट्स की मेन्युफेक्चरिंग को इस देश में बढ़ावा देने की बजाए अब बजट भाषण के माध्यम से इक्विपमेंट के इम्पोर्ट पर ड्यूटी को 40 परसेंट से घटाकर 30 परसैंट और 30 परसैंट से घटाकर 20 परसैंट किया गया है, जिसके कारण मैं समझता हूं कि हमारी आई०टी०आई० जैसी पब्लिक सैक्टर वाली इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आप यह आवश्यक नहीं समझते कि यह जो मैन्युफेक्चरिंग बेस इंडिया में मौजूद है, इसको भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की फेसिलिटी, जो केवल सर्विसिस को दी गई है—बेसिक और सेल्युलर को, वह आगे भी, इनको भी मिलनी चाहिए?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, अग्रवाल जी के अनुपूरक प्रश्न के थोड़े अंश से हम भी सहमत हैं। उसमें जो आपने कहा कि मोबाइल, ट्रंक सर्विसिज़ और पेजिंग, हम समझते हैं कि इनको भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में लिया जाना चाहिए था और हम आपकी भावनाओं को अपनी सिफारिश के साथ वित्त मंत्री जी के पास भेज देंगे। इसके साथ-साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर है हमारे यहां, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर में नहीं लिया गया है लेकिन कस्टम ड्यूटी और ऐक्साईज ड्यूटी में उनको भी छूट दी गई है। उसकी बहुत बड़ी सूची होगी लेकिन खास तौर से जैसे ऑप्टिकल फाईबर है, इसमें 25 परसेंट कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई है। और भी दूसरी चीजें हैं, Specified raw materials for the manufacture of FRP rods. इसमें भी दी गई है। टी०आर०पी० रौड्ज़, इसमें भी 20 परसेंट किया है। इसी तरह से कैपिटल गुड्ज़ फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, इसमें भी 20 परसेंट कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। तो इस तरह से कस्टम ड्यूटी और ऐक्साईज़ ड्यूटी में रिबेट दिया गया है लेकिन जो ऐस्टेब्लिशड कंपनीज़ हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर में उन्हीं को लिया गया है और उनको इन्कम टैक्स में 5 साल तक छूट मिलेगी और 5 साल के बाद भी उनको 25 परसेंट की छूट मिलेगी।

अग्रवाल जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मूल रूप से आपको यह प्रश्न वित्त मंत्री जी से पूछना चाहिए था। आपकी जो भावनाएं हैं ट्रंक मोबाईल सर्विसेज़ के बारे में और पेजिंग सर्विसेज़ के बारे में, यह हम वित्त मंत्री जी को अपनी सिफारिश के साथ पहुंचा देंगे।

श्री सतीश अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने के लिए जो इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चर है अपने देश में, इसको भी इन इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के ऐक्जम्प्शन के लिए शामिल किया जाना

चाहिए। अन्यथा परिणाम क्या होगा कि आपकी सारी योजनाएं कागजों पर धरी रह जाएंगी। अगर टेलीफोन ही नहीं है, अगर केबल्स नहीं हैं, स्विच-गीयर्स नहीं हैं, लाईंस नहीं हैं, असेंबलीज़ नहीं हैं तो फिर इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए अगर आप वास्तविक रूप से इसको करना चाहते हैं तो इनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि आपने इसकी सिफारिश पहले की थी या नहीं की थी। हो सकता है कि आपके विभाग ने उतना ही लिखा हो और उन्होंने उतना मान लिया। आज आपने आश्वासन दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं कि आप इस मामले को उनके साथ टेक-अप करेंगे।

क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आई०टी०आई० जो हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, क्या यह सही है कि डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स न होने की वजह से, वहां से माल न खरीदने के कारण और इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन होने के बाद उसका जो कैपेसिटी यूटिलाईजेशन है, वह बिलो दि ऐवरेज लेवल है। अगर है तो कितना है? कितना कम है, कितना उसमें घाटा है और उसको मजबूत बनाने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। यह मैं एक इंस्टेंस दे रहा हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, यह सही है कि आई०टी०आई० इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पब्लिक सैक्टर यूनिट है और पिछले दिनों उसको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन इस वर्ष हमने उसके लिए काफी धन की व्यवस्था की है। अभी एक और पैकेज उनको देने पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही उस पर निर्णय हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो इक्विपमेंट्स आई०टी०आई० बनाता है उसमें हमने 30 परसेंट रिज़र्वेशन कर दिया है और 30 परसेंट रिज़र्वेशन के अंगेस्ट हम उनके लिए 75 परसेंट ऐडवांस का प्रोविजन कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि आई०टी०आई० मजबूत हो और उसके लिए हम अपने सीमित संसाधनों के रहते हुए जो कर सकते हैं, उनमें हम किसी तरह की कंजूसी नहीं कर रहे हैं।

आपने पहले यह पूछा था कि आई०टी०आई० को इससे क्या लाभ मिलेगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आई०टी०आई० में भी तमाम सामान आयात किया जाता है इक्विपमेंट बनाने के लिए। इसमें उनको भी छूट मिलेगी। चूंकि अब टेलीकॉम उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में आ गया है और कुछ टैक्स की छूट भी मिल गई है, इससे सबसे बड़ा लाभ उनको मिलेगा वी०एस०एल० में। अनुमान है कि अगले साल हमको करीब 75 करोड़ रुपए का लाभ वी०एस०एल० में होगा।

श्री सतीश अग्रवाल: उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। मेरा वह प्रश्न नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो टेलीकॉम पालिसी थी, उसमें यह लिखा हुआ है कि—

"Taking into account India's size and development, it is necessary to ensure that India emerges as a major manufacturing base and a major exporter of telecom equipments."

उस दृष्टि से मैं आई०टी०आई० की हालत पूछना चाहता हूं। क्या वहां बिलो दि ऐवरेज कैपेसिटी यूटिलाईजेशन नहीं है? अगर है तो उसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? बाकी भी आपके यहां जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में भी बताइए। अगर टेलीफोन नहीं हैं, इक्विपमेंट नहीं हैं तो आप करेंगे क्या? ये टारगेट कैसे पूरे होंगे?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, हमने अभी बताया था। सम्भवतः माननीय अग्रवाल जी को.....**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल: वह तो बजटरी सपोर्ट दे रहे हैं। मेहरबानी कर रहे हैं कि इतना दे देंगे, इतना दे देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: नहीं-नहीं, उनको हम फाइनेंसियली सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनकी जो मैन्युफेक्चरिंग होती है उसको हम 30 परसेंट रिजर्व कर रहे हैं कि 30 परसेंट हम सिर्फ आई०टी०आई० से ही लेंगे और उसके अगेंस्ट हम उनको 75 परसेंट एडवांस करेंगे। तो आई०टी०आई० को मजबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। उसमें और भी जो आप सुझाव देंगे हम आपसे अलग से बैठकर बात कर लेंगे। आई०टी०आई० मजबूत हो इसमें हमारी कोशिश है।....**(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल: अब मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

SHRIMATI MARGARET ALVA: I had raised the question of ITI earlier in this House and I had been assured that ITI was going to receive special attention. It has been, if I may say so, the prime leading institutions in this country for telecom. Sir, what I am saying is, it is not just enough to give some kind of reservation of 30 per cent for products or some subsidy. What I am saying is, there is a need to modernise ITI with the new technological inputs to make it capable of

meeting the challenges of the new communication revolution in the country. That is what I am talking about.

साहब। आप तो दो साल पैसा देंगे, बाद में बोलेंगे कि बजट में कोई पैसा नहीं है तो बंद करो। पैसे से या सब्सिडी से तो यह काम होने वाला नहीं है आई०टी०आई० का। आई०टी०आई० को मॉडर्नाइज करने की बात है। बंगलौर में ही नहीं दूसरे हमारे स्टेट में भी इसके दो यूनिट हैं। मैं यह चाहती हूं आपसे कि इंवेस्टमेंट करिए। बेसिक इंवेस्टमेंट इसको मॉडर्नाइज करके जो अभी बाहर से हमें कम्पटीशन आ रहा है उसको तो हम बिल्कुल आई०टी०आई० से मीट कर सकते हैं। यह नहीं कि आप हमारी पूरी फैक्टरी को बंद करिए क्योंकि पैसे नहीं है और वह तो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और ऐसे सब कुछ खत्म कर दें।

I want an assurance from you that ITI will get the necessary investment inputs to modernise it, bring the latest technology and be able to not just meet the domestic demands but also become an exporter in the international area. Thank you. यह एश्यूरेंस पहले इस हाऊस में दिया गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, जो बहन आल्वा जी ने प्रश्न किया है हम भी उसी भावना के हैं और आप आश्वासन चाहती हैं तथा जो बहुत गंभीरता से आपने कहा है उस पर हम विचार करेंगे।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: सर, एश्यूरेंसेज ऐसे ही देते रहते हैं, कुछ हुआ नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: हमने किया है और कोशिश कर रहे हैं। आई०टी०आई० के बारे में जितना आप चाहती हैं उससे भी ज्यादा हमारी इच्छा है कि उसको मजबूत किया जाए। उसमें जो भी हम कर सकते हैं उस पर विचार करेंगे।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, I think the steps taken to partially announce the telecom sector as an infrastructure sector smacks of the same kind of ignorance about the specific nature of requirements of the sector. Now, Sir, we have been discussing in the last few days in this House about the major problems of the telecom sector in the country today. The Minister has also given a Statement the other day about the problem of the running of the village telephone system. Earlier also the Minister had told the House that major shortfall is in terms of providing village connectivity. Now the Minister has also told the House that the major problem of reaching the target and ensuring the quality of the services has arisen because of a major problem which has developed in the equipment sector, because of corruption as well as the number of technologies that were allowed in the past few years. As a result of that we are seeing that there is a slow-down in the production process, in the manufacturing process and the companies, both public and private, operating in this sector are affected. So what was really necessary was also to include the equipment manufacturing units as part of this benefit to announce the sector as an infrastructure sector. Will the Minister kindly explain why the actual aspect of declaring the telecom as an infrastructure sector has not been addressed as such?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, आधारभूत ढांचे में इसलिए रखा गया है कि हमारे यहां जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हमारे यहां उत्पादन बढ़े और उत्पादकों को उससे थोड़ी राहत मिले। जहां तक माननीय बसु जी ने ग्रामीण टेलीफोन के बारे में बात उठाई थी, वह इस प्रश्न से संबंधित तो नहीं है लेकिन हमने पहले ही इस सदन में बयान दिया था कि हम भी इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और हमने, इस टेक्नॉलाजी में कोई दोष था या नहीं था, उसमें कोई फाइनेंशियल इर्रेग्युलेरिटी हुई या नहीं हुई, इसके लिए पूरे मैटर को सी०बी०आई० के सुपुर्द कर दिया है। साथ ही साथ जो हमें इनफॉर्मेशन मिली थी फील्ड से, उससे भी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि ग्रामीण टेलीफोन ठीक हैं या नहीं हैं तो उसको भी हमने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को सौंप दिया है कि वह हमें बताए कि कितने ग्रामीण टेलीफोन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, that was not my question. My question specifically was that problems had arisen out of the slow-down in the telecom, equipment manufacturing sector. I said that because of this it was all the more necessary that equipment manufacturing sector was also regarded as one of the infrastructural sectors. Taking advantage of

that, equipment manufacturers could come out of their present problems which again arose out of the decisions on quality taken in the past.

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन्, मंत्रालय ने तो सिफारिश की थी, निर्णय वित्त मंत्रालय ने लिया है और उसमें दो सर्विसेज को इनफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लिया गया है। बासी सेक्टर्स में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज़ ड्यूटी की छूट दी गई है और उससे भी उत्पादन को ही बल मिलेगा।

श्रीमती वीणा वर्मा: सर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि टेलीफोन को प्राइयॉरिटी सेक्टर में लेकर, उसमें सेल्युलर टेलीफोन को, बेसिक सर्विस इंडस्ट्रीज़ इनफ्रास्ट्रक्चर को फिस्कल बेनिफिट्स की सुविधा मिलेगी। अभी कल ही कम्प्यूटर सम्राट बिल गेट्स हमारे देश में आए और उन्होंने धूम मचा दी है "माइक्रोसॉफ्ट 95" के द्वारा। हमारे प्रधान मंत्री जी से भी वे मिले हैं और एक बात जो अखबारों में आई है कि दूरसंचार, शिक्षा और सूचना टेक्नालॉजी का यदि सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मान्य बात है कि लोगों का जीवन-स्तर सुधरेगा इस देश में। सब जानते हैं कि टेलीफोन कम्प्यूटर चलाने के लिए टेलीफोन की बहुत आवश्यकता है और ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा उसको यूज़ करते हुए कम्प्यूटर चलाया जाए, गांव-गांव तक पहुंचे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार होने वाला है और ऑप्टिकल फाइबर तो है भी कम खर्चीला। तो कम्प्यूटर को या सॉफ्टवेयर को ज़रूरी इनफ्रास्ट्रक्चर मानते हुए टेलीफोन से जोड़ने के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ को भी इस बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर में लाने के बारे में जैसे सेल्युलर को लाने की आप सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: श्रीमन् बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, इसका फैसला तो वित्त मंत्रालय करता है। आपकी भावनाओं को भी .....(**व्यवधान**).....

श्रीमती वीणा वर्मा: आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको बेनीफिशरीज़ में लाने के लिए?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा: आपकी भावनाओं पर विचार करके अगर हमारे विभाग ने आवश्यक समझा तो उसे हम वित्त मंत्रालय को रेफर कर देंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा: शुक्रिया।

Visa Granted to Pakistani Citizens

*166. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of entry visas granted to Pakistani citizens since 1991-92;

(b) whether any classified information is available on the social background of the individuals who have been granted visas; and

(c) whether a further liberalisation of visas is being considered to increase Indo-Pakistan amity and understanding at the grassroot level?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) The year-wise figures in respect of the visas issued to Pakistani nationals since 1991 are as below:—

1991 :	194,182
1992 :	178,431
1993 :	45,927
1994 :	34,574
1995 :	24,218
1996 :	40,583

(b) No, Sir.

(c) In pursuance of our policy of encouraging people-to-people contacts and promoting greater interaction among scholars, intellectuals, journalists, writers, artists, businessmen and others, Government have unilaterally eased the issuance of visas to Pakistani nationals. As a consequence, there has been a substantial increase in the number of visas issued to Pakistani nationals. Further liberalisation will be considered when appropriate.

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Setting Up of Port Facilities

*163. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state: